देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 12.12.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए 210 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी।
- राज्य की सभी जेलों में 'एक जेल–एक प्रोडक्ट' की अवधारणा विकसित करने और बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एस०आई०आर की तैयारियों की समीक्षा की।
- नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में चार दिवसीय पक्षी और जैव विविधता सर्वेक्षण शुरू।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन कार्यों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 210 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं।

आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए 71 वाहनों की खरीद को स्वीकृति दी गई है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग–109 के पुनर्निमाण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित योजनाओं के तहत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में दो संपर्क मार्गों के निर्माण, तथा डीडीहाट में नैनीपातल से भगवती मंदिर तक सीसी संपर्क मार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

चम्पावत जिले के लिये उद्यानिकी विकास तथा पूर्णागिरी तहसील में मिनी विकास भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी धनराशि नाबार्ड मद से प्रयोग की जाएगी।

श्री धामी ने देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र की काण्डी, चामा और गाता ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टिन शेड निर्माण तथा उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में 300 हैंडपंप स्थापना के कार्यों को भी स्वीकृति दी।

निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी जेलों में 'एक जेल–एक प्रोडक्ट' की अवधारणा विकसित करने और बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई जेल विकास बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि जेलों के विकास के लिए राज्य का अपना मॉडल तैयार किया जाए और आईटीआई के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री ने जेलों में बनाए गए उत्पादों का उपयोग सरकारी कार्यालयों में करने और भोजन व्यवस्था की समय–समय पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कारागार सितारगंज, जिला कारागार अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, उप–कारागार हल्द्वानी और रूड़की में लॉन्ड्री मशीनें स्थापित की जाएंगी। देहरादून और हरिद्वार जेलों में इसके अच्छे परिणाम सामने आए थे। मुख्यमंत्री ने कारागारों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा।

बैठक में सितारगंज की खुली जेल में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र स्थापना पर सहमति बनी। सितारगंज और हरिद्वार जेलों में मशरूम फार्मिंग की अनुमति भी दी गई। बताया गया कि हरिद्वार, अल्मोड़ा, सितारगंज और हल्द्वानी जेलों में बेकरी यूनिट से लगभग 12 लाख रुपये की आय अर्जित हुई है, जबकि सितारगंज खुली जेल की गौशाला से करीब 10 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

हड़ताल स्थगित

टिहरी गढ़वाल के पिलखी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है। शासनादेश जारी होने के साथ ही कुल 36 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें 26 नियमित और 10 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। ये पद फिलहाल 28 फरवरी 2026 तक स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक तैनाती, भवन सुधार और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मैदानों के स्तर तक विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। पिलखी में 30 बेड का सीएचसी बनने से हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और नए पदों से स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि 'हर घर स्वास्थ्य, हर व्यक्ति स्वस्थ' के संकल्प के साथ सरकार तेजी से काम कर रही है और यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से लंबित अपेक्षा को पूरा करेगा।

समीक्षा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से राज्य के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर) की तैयारियों, जिला और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी स्तर पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, तथा बूथ अवेयरनेस ग्रुप की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि बूथ लेवल ऑफिसर "बीएलओ आउटरीच अभियान" के तहत अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से नियमित संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करें। जिलाधिकारियों को बीएलओ के नियमित भ्रमण की प्रभावी निगरानी करने और उसकी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वोटर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी लेने वाले मतदाताओं की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए।

हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत देहरादून में बन रहा स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केंद्र तेजी से आकार ले रहा है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशालय परिसर में निर्माणाधीन केंद्र का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति पर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टमटा और नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह मौजूद रहे।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर निर्माण का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य निर्धारित गति से चल रहा है। उम्मीद है कि यह केंद्र जनवरी 2026 के अंत तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करेगी। राज्य सरकार इसके संचालन के लिए अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपात प्रतिक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दे रही है, ताकि केंद्र शुरू होते ही पूरी क्षमता से काम कर सके।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह केंद्र, प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देगा और आपदा एवं महामारी के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाएगा। यह केंद्र स्वास्थ्य निगरानी, डेटा विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा, जिससे जिलों के बीच समन्वय बेहतर होगा।

सर्वेक्षण

नैनीताल स्थित नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में चार दिवसीय पक्षी और जैव विविधता सर्वेक्षण शुरू हो गया। यह सर्वे 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नौ राज्यों से आए 34 बर्ड वॉचर हिस्सा ले रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि इस सर्वे से प्रभाग में पक्षियों की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की वास्तविक स्थिति का अद्यतन वैज्ञानिक डेटा मिलेगा, जो भविष्य की संरक्षण नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सर्वे में अलग–अलग क्षेत्रों में बर्ड वॉचरों की तैनाती की गई है।

कार्यशाला

अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लॉक के खूंट गांव में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की सहायता से नाबार्ड वित्तपोषित परियोजना के तहत यह कार्यशाला आयोजित हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि को औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से उपयोग में लाना और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाना है।

कार्यशाला में परियोजना अन्वेषक डॉ. सतीश चंद्र आर्य ने औषधीय प्रजातियों से मिलने वाले प्राकृतिक और आर्थिक लाभों की जानकारी दी। सहायक खंड विकास अधिकारी रमेश सिंह कनवाल ने मनरेगा के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सहायता के बारे में बताया। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के मास्टर ट्रेनर संतोष सिंह ने किसानों को हर्बल संस्थान में पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई।

इसके बाद डॉ. आशीष पांडेय ने औषधीय पौधों की खेती, तकनीकी प्रबंधन, देखभाल, सिंचाई, उपयोग और बाजार मूल्य पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर–

आउटसोर्स वनकर्मियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राहत दी है। यह ख़बर लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित है। नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– आउटसोर्स वन कर्मियों को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में दिया फैसला, सरकार को नियमित सेवा लेने का आदेश।

पीआरडी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित रैतिक परेड में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है–पीआरडी जवानों के लिए बनेगा प्रशिक्षण संस्थान।

वन्य जीव पीड़ित परिवारों के लिए आजीविका नीति बनेगी, हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार वन्यजीव हमलों में परिवार के कमानें वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी।